

संपादकीय

डिग्री मांगना जुर्म है!

यह बात किसी तर्क से गले नहीं उतरती कि केजरीवाल ने तुच्छ याचिका के जरिए कोर्ट का समय खराब किया। इसके बावजूद हाई कोर्ट ने ना सिर्फ सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया, बल्कि केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया।

गुजरात हाई कोर्ट का फैसला हैरान करने वाला है। यह तथ्य गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की शैक्षिक डिग्री मांगने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट नहीं गए थे। केजरीवाल ने अर्जी केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के पास दी। सीआईसी ने केजरीवाल की अर्जी को वाजिब माना और संबंधित यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री की डिग्री याचिकाकर्ता को देने को कहा। केजरीवाल की भूमिका यहीं थम गई। हाई कोर्ट का दरवाजा यूनिवर्सिटी ने खटखटाया। उसने सीआईसी के आदेश को चुनौती दी। इस क्रम में केजरीवाल को दूसरा प्रतिवादी जरूर बनाया गया। लेकिन यह बात किसी तर्क से गले नहीं उतरती कि केजरीवाल ने तुच्छ याचिका के जरिए कोर्ट का समय खराब किया। इसके बावजूद हाई कोर्ट ने ना सिर्फ सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया, बल्कि केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। इस लिहाज से उचित तो यह होता कि कोर्ट सीआईसी पर भी जुर्माना लगाता! आखिर यूनिवर्सिटी को डिग्री उपलब्ध कराने का आदेश तो सीआईसी ने दिया था! प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर बहस अलग है।

भारतीय सविधान कम पढ़े-लिखे और अति विद्वान में फर्क नहीं करता। दरअसल, ऐसी मिसालें हैं, जब औपचारिक शिक्षा ना होने के बावजूद अनेक व्यक्तियों ने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। इसलिए केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के पढ़े-लिखे होने को लेकर जो बहस छेड़ी है, उस पर उनसे असहमत होने के भी पर्याप्त तर्क मौजूद हैं। लेकिन किसी डिग्री या किसी शैक्षिक स्थिति को छिपाने का कोई तर्क नहीं हो सकता। खास कर उस व्यक्ति के लिए जो सार्वजनिक जीवन में हो। बल्कि बेहतर यह होता कि प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सच सार्वजनिक करते हुए इस बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता। जबकि अब केजरीवाल और उनकी पार्टी को यह कहने का मौका मिला है कि प्रधानमंत्री के अनपढ़ या कम पढ़ा-लिखा होने संबंधी उनका दावा सच साबित हो गया है! बहरहाल, बिना इस सियासी बहस में जाते हुए भी यह अवश्य कहा जाएगा कि हाई कोर्ट का फैसला समस्याग्रस्त है और उससे न्यायपालिका के बारे में फैल भ्रम और मजबूत होंगे।

मार्च तिमाही में रिकॉर्ड 12.3 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं

नई दिल्ली। पिछले वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में रिकॉर्ड नई परियोजनाएं आईं, जो कुछ बड़ी निवेश योजनाओं का नतीजा हो सकती हैं। मार्च 2023 में समाप्त तिमाही के दौरान 12.3 लाख करोड़ रुपये की नई परियोजनाएं आईं।



परियोजनाओं पर नजर रखने वाले सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकॉनमी (सीएमआईई) से प्राप्त पूंजीगत निवेश करने में काफी सक्रियता बरत रही हैं। नई परियोजनाओं में सरकारी सड़क परियोजनाएं और कंपनियों द्वारा लगाए जाने वाले नए संयंत्र दोनों ही शामिल हो सकती हैं या वस्तु एवं सेवा मुहैया कराने के लिए क्षमता विस्तार इसकी वजह हो सकती है। समझा जा रहा है कि नई परियोजनाओं में बढ़ोतरी की मुख्य वजह वस्तु एवं सेवा आपूर्ति ढांचा मजबूत बनाने पर आया खर्च है।

बैंक ऑफ बड़ौदा में मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि परिवहन क्षेत्र में 7.5 लाख करोड़ रुपये के ऑर्डर का नई परियोजनाओं में हुई वृद्धि में शायद प्रमुख योगदान रहा होगा। इससे पहले 2009 में एक तिमाही में 10 लाख करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं आई थीं। सबनवीस ने कहा कि यह परिवहन क्षेत्र में आया सबसे बड़ा ऑर्डर है। एचडीएफसी सिस्केरिटीज में प्रमुख (खुदरा शोध) दीपक जसानी के अनुसार यह बढ़ोतरी तब हुई है, जब निजी क्षेत्र की कंपनियां पूंजीगत निवेश करने में काफी सक्रियता बरत रही हैं। नई परियोजनाओं में सरकारी सड़क परियोजनाएं और कंपनियों द्वारा लगाए जाने वाले नए संयंत्र दोनों ही शामिल हो सकती हैं या वस्तु एवं सेवा मुहैया कराने के लिए क्षमता विस्तार इसकी वजह हो सकती है। समझा जा रहा है कि नई परियोजनाओं में बढ़ोतरी की मुख्य वजह वस्तु एवं सेवा आपूर्ति ढांचा मजबूत बनाने पर आया खर्च है।

के अनुसार परिवहन के अलावा अभियांत्रिकी, वाहन और ई-वाहन खंड से जुड़ी कंपनियों तथा सीमेंट क्षेत्र में निवेश आ रहा है। उन्होंने कहा, 'निजी क्षेत्र से पूंजीगत निवेश अब भी सुस्त रहता है आ रहा है। मगर पिछली दो-तीन तिमाहियों की तुलना में इसमें सुधार जरूर हुआ है।'

जब स्थापित क्षमता मांग पूरी करने के लिए नाकाफी होती है तो कंपनियां नए उत्पादन संयंत्र तैयार करने में लग जाती हैं। फिलहाल स्थापित क्षमता का करीब एक चौथाई हिस्सा अभी इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ऑर्डर बुक, भंडार एवं क्षमता उपयोगिता सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 की दूसरी तिमाही में क्षमता इस्तेमाल बढ़ा जरूर है। सर्वेक्षण में कहा गया है, 'वित्त

डेरी उत्पादों के आयात की तैयारी, दुग्ध उत्पादन में स्थिरता के कारण आपूर्ति पर बढ़ रहा दबाव

नई दिल्ली। लगभग एक दशक के बाद भारत को दुग्ध उत्पादों के आयात पर विचार करना पड़ सकता है। देश में दुग्ध उत्पादन ठहर जाने के कारण आपूर्ति में दिक्कत आ रही है। इसलिए सरकार बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जरूरत पड़ने पर आयात की भी सोच सकती है।

सिंह ने कहा, 'दक्षिणी राज्यों में इस समय दुग्ध उत्पादन चरम पर रहता है। वहां दुग्ध के स्टॉक का जायजा लेने के बाद जरूरत पड़ने पर सरकार मक्खन और घी जैसे डेरी उत्पादों के आयात की मंजूरी दे सकती है।' आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में 2021-22 में 22.1 करोड़ टन दुग्ध उत्पादन हुआ, जो पिछले वर्ष के 20.8 करोड़ टन से 6.25 फीसदी अधिक है। पिछले 15 महीनों में देश में दुग्ध की कीमतें 12 से 15 फीसदी बढ़ गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कीमत बढ़ने का सिलसिला अक्टूबर 2023 से पहले नहीं रुकेगा। दूध की मुद्रास्फीति



सितंबर 2022 में 5.55 फीसदी से बढ़कर फरवरी 2023 में 10.33 फीसदी हो गई है।

सचिव ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में मवेशियों में लंपी त्वचा रोग के कारण देश में दुग्ध का उत्पादन प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि उत्पादन स्थिर रहने के बावजूद इस दौरान घरेलू मांग में 8 से 10 फीसदी की वृद्धि हुई। कोविड

महामारी के बाद भी दूध की मांग बढ़ी है। सिंह ने कहा, 'देश में दूध की आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं है। स्किम्ड मिल्क पाउडर (एमएमपी) का पर्याप्त भंडार है। मगर वसा, मक्खन एवं घी जैसे डेरी उत्पादों का भंडार पिछले साल के मुकाबले कम है।' सिंह ने जोर देकर कहा कि दक्षिणी राज्यों में दूध के भंडार की स्थिति समझने के बाद जरूरत पड़ी तो सरकार मक्खन और घी जैसे डेरी उत्पादों के आयात के लिए हस्तक्षेप कर सकती है। दक्षिणी राज्यों में अब दुग्ध उत्पादन का पीक सीजन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में कमी अपेक्षाकृत कम रहेगी।

फल हेल्थ के लिए होता है फायदेमंद, जानें खाने का सही समय

फल हमारे शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक और सेहतमंद कहे जाते हैं। इनसे हमें ढेर सारे मिनिरल्स और विटामिन के साथ साथ कैलोरी भी मिलती है। लेकिन अधिकतर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि फल खाने का सही समय क्या है। फल कब खाना चाहिए, खाने से पहले या खाने के बाद, इसलिए इस भ्रम को आज दूर करने की कोशिश करते हैं। चलिए जानते हैं कि फल खाने का सही समय क्या है?



हो जाता है और पेट से जुड़ी कई दिक्कतें जैसे अपच, अफारा, एसिडिटी, मरोड़ और कब्ज आदि की संभावना पैदा हो जाती है।

खाने के पहले और बाद खाने के फायदे और नुकसान

'हेल्थ एक्सपर्ट' कहते हैं कि फल भोजन करने से आधा से एक घंटा पहले खाए जाएं तो शरीर को बहुत पोषण देते हैं। यही फल अगर आप खाने के बाद खाते हैं तो शरीर में भोजन के साथ फलों की एक्स्ट्रा कैलोरी चली जाती है, जिससे सेहत को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। बेहतर होता है कि फलों को खाने के साथ और खाने के तुरंत बाद ना खाएं। फल खाने का सही समय सुबह, दोपहर और शाम को होता है, रात को सोने से तुरंत पहले भी फलों का सेवन नहीं करना चाहिए।

खाने के तुरंत बाद फल खाने के नुकसान

दखा जाए तो फलों में फ्रुक्टोज होता है जो जल्दी पचता है, अगर भोजन के तुरंत बाद फल खाते हैं तो फ्रुक्टोज जल्दी पचता है और पेट में पहले से गया भोजन पचने में काफी दिक्कत आती है। भोजन के तुरंत बाद खाना खाने से शरीर में कई तरह के टॉक्सिन एकत्र होने की बात की जाती है, इसका असर पेट के साथ साथ त्वचा पर भी दिखता है।

भोजन के बाद फल खाने के नुकसान

'हेल्थ एक्सपर्ट' सलाह देते हैं कि भोजन करने के तुरंत बाद फल खिलकुल ना खाएं, दरअसल भोजन के जरिए पहले ही शरीर काफी सारी कैलोरी ले चुका होता है, जो पचाए बिना अगर आप भोजन के तुरंत बाद फल खाते हैं तो शरीर को एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक डीलना पड़ता है, इससे पाचन तंत्र पर दोहरा भार पड़ता है और वो इतनी सारी कैलोरी को एक साथ पचा नहीं पाता, भोजन के तुरंत बाद फल खाने से पाचन तंत्र खराब

फल खाने का सही समय क्या है

इस पर एक्सपर्ट कहते हैं कि फल तब खाएं जब आप कुछ देर पहले या बाद में भोजन ना कर रहे हों। यानी दिन में 10 से 12 बजे के बीच फल खाने का सही समय है, इस समय आप आराम से फल खा सकते हैं और इनका पूरा पोषण आपके शरीर को मिलेगा। शाम के समय भी फल खाने का सही समय है, ये समय चार से सात बजे तक का हो सकता है, दिन में अगर आप 11 बजे के आस पास फल खाते हैं तो आपकी चटर पटर की भूख भी शांत होती है और फलों के जरिए आपको ढेर सारा फाइबर भी मिलता है जिससे पाचन तंत्र मजबूत होता है।

एफवाई24 में खुदरा महंगाई दर रहेगी 5.2 फीसदी 0-आरबीआई एमपीसी सीट 2023

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष (2023-24) के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को मामूली घटाकर 5.2 प्रतिशत कर दिया है। फरवरी की मौद्रिक समीक्षा में इसके 5.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने सतर्क किया है कि अभी महंगाई से 'लड़ाई' समाप्त नहीं हुई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिशाली दास ने गुरुवार को 2023-24 की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए कहा कि तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक के कच्चे तेल के उत्पादन को घटाने के फैसले से मुद्रास्फीति का परिदृश्य गतिशील बना हुआ है। दास ने कहा कि सामान्य मानसून के बीच यदि कच्चे तेल के दाम औसतन 80 डॉलर प्रति बैरल रहते हैं, तो चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति 5.2 प्रतिशत रहेगी। जून तिमाही में मुद्रास्फीति के 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सितंबर और दिसंबर तिमाही में यह बढ़कर 5.4 प्रतिशत पर पहुंच सकती है।

आरबीआई ने रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा, 2023-24 में वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में जारी पुनरुद्धार को और गति देने के लिये गुरुवार को नीतिगत दर रेपो में और वृद्धि नहीं की और इसे 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। वहीं चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया है।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सोमवार से शुरू हुई तीन दिन की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिशाली दास ने कहा कि एमपीसी ने अर्थव्यवस्था में जारी पुनरुद्धार को बरकरार रखने तथा उसे और गति देने के लिये आम सहमति से नीतिगत दर को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखने का निर्णय किया है। रेपो दर वह ब्याज दर है, जिसपर वाणिज्यिक बैंक अपनी फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिये केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं, इससे पहले, आरबीआई मुख्य रूप से मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिये



मनीषा कल्याण ने साइप्रस में रचा इतिहास, यूरोप में लीग खिताब जीतने वाली बनीं पहली भारतीय



नई दिल्ली। स्टार महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण यूरोप में लीग का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। मनीषा इससे पहले 2021 में एएफसी चैंपियंस लीग मैच में और ब्राजील की एक वरिष्ठ राष्ट्रीय टीम के खिलाफ गोल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनीं थीं। उन्होंने कहा, 'मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ कि मैं यूरोप में लीग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरा काम हो गया, मैं यहां पहुंच गई हूँ, अब यह खत्म हो गया है। इससे जो सकारात्मकता उत्पन्न हुई है, वह मुझे केवल कड़ी मेहनत करने और अधिक हासिल करने की प्रेरणा दे रही है।' मनीषा अगस्त 2022 में साइप्रस चली गईं और उन्हें यूईएफए चैंपियंस लीग के लिए क्वालीफायर में खेलने का मौका मिला। यह वहां से उनके सीखने की अवस्था थी। यूसीएल क्वालीफायर के दौरान और घरेलू स्तरीय की शुरुआत के दौरान उन शुरुआती महीनों में उन्हें संघर्ष करना पड़ा और इसका एक बड़ा हिस्सा उस तरह की प्रणाली से उपजा था जिससे वह आई थीं। उन्होंने कहा, मुख्य अंतर

पिछले साल मई से लेकर कुल छह बार में रेपो दर में 2.50 प्रतिशत की वृद्धि कर चुका है।